Polity

Explanation (TEST : 01)

06 July, 2018 (06:30 pm)

1. (c) इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर बनाम भारत संघ, 1985 वाद में न्यायालय ने विचार और अभिव्यक्ति के अन्तर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया। अत: कथन 1 सत्य है। राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति बिना राष्ट्रपति के सहमति से किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं करेगा। अत: कथन 2 सत्य है। अत: अभीष्ट उत्तर (c) होगा।

2. (a) **सही सुमेलित हैं-**

अनुच्छेद 19(a) - विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19(b) - शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19(c) - सहकारी संस्था/समिति बनाने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19(d) - भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार

3. (d) प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य है, जबकि प्रश्न में असत्य कथन पूछा गया है। अत: अभीष्ट उत्तर (d) होगा।

4. (d) भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 19(1) के उपखण्ड(क) के अन्तर्गत शामिल सीमाएं हैं-

- भारत की सम्प्रभुता और अखण्डता,
- राज्य की सुरक्षा,
- विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध,
- लोक व्यवस्था,
- शिष्टाचार अथवा सदाचार (नैतिकता),
- न्यायालय की अवमानना,
- मानहानि,
- अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन।

अत: अभीष्ट उत्तर (d) होगा।

5. (a) भारत में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन घृणावाक् की स्वतंत्रता नहीं है। घृणावाक् से तात्पर्य ऐसी अभिव्यक्ति जो समाज में विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने का कार्य करती है, मानहानि की ओर ले जाती है, व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाती है और सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करती है, आदि से है। अत: कथन 1 सत्य है। भारतीय संसद ने लाभ का पद अधिनियम, 2006 पारित कर 56 (न कि सौ से अधिक) पदों को लाभ के पद को अपवाद माना है। अत: कथन 2 असत्य है। अत: अभीष्ट उत्तर (a) होगा।

6. (d) प्रश्न में दिए गए दोनों वाद सत्य है, जबकि प्रश्न में असत्य कथन पूछा गया है। अत: अभीष्ट उत्तर (d) होगा।

7. (c) प्रश्न में दिए गए दोनों कथन द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) से संबंधित है। अत: अभीष्ट उत्तर (c) होगा।

8. (d) भारतीय संसद ने 77वें संविधान संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति (न कि अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। अत: कथन 1 असत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-17 (न कि अनुच्छेद-16) में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अत: कथन 2 असत्य है। अत: अभीष्ट उत्तर (d) होगा।

9. (b) इन्द्रा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का निर्णय-

- न्यायालय ने आरक्षण को सही माना। आरक्षण संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का विरोधी नहीं है।
- आरक्षण का आधार जाति को बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन ही मुख्य पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन मुख्य पिछड़ापन नहीं है।
- पिछड़े वर्गों में सम्पन्न तबके (क्रीमीलेयर) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। (OBC+SC+ST)
- पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा।
- आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।

अत: अभीष्ट उत्तर (b) होगा।

10.(d) भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम/जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत छुआछूत को दण्डनीय अपराध घोषित किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित को अपराध मानता है-

- जाति के आधार पर अपमानसूचक शब्द कहना,
- किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से रोकना,
- अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टलों में सार्वजनिक हित के प्रवेश से रोकना,
- किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोकना अथवा कहीं पर पूजा करने से रोकना,
- परम्परागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर 'अस्पृश्यता' को न्यायोचित ठहराना,
- प्रत्यक्ष या अप्रत्या रूप से अस्पृश्यता को मानना,
- किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना।

अत: प्रश्न में दिए गए तीनों कथन सत्य है। अत: अभीष्ट उत्तर (d) होगा।

* * *

GS World
Committed To Excellence

ANSWER KEY
Polity (06 July, 2018) Test No. 01

1.	(c)	2.	(a)	3.	(d)	4.	(d)	5.	(a)	6.	(d)	7.	(c)	8.	(d)	9.	(b)	10.	(d)